>

Title: Need to provide more assistance and facilities to the differently abled persons in the country.

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे तेज रफ्तार में चल रही गाड़ियों के कारण तथा विभिन्न बीमारियों के चलते विकलांग्ता का प्रतिशत बढ़ रहा है। भारत सरकार द्वारा जो विकलांग कल्याण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनमें न तो उनको पर्याप्त पेंशन मिल पा रही है और न ही उनके द्वारा ब्लॉक या जिले में शिक्षा देने के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था है। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा स्कूलों का प्रबंध न होने के कारण वे अशिक्षा का भी शिकार होते जा रहे हैं।

प्राइवेट संस्थाएं इन विकलांगों को काफी हद तक सुविधा देना चाहती हैं। उन्हें शिक्षा देना चाहती हैं, समाज की बराबरी में लाना चाहती हैं। लेकिन जो लोग विकलांग विद्यालय खोलकर विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं, अगर उनके पास कक्ष नहीं हैं तो उसके लिए भारत सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करे।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप अपनी मांग रखिए।

श्री राजाराम पाल: उनके लिए एलैम्बको जैसा संस्थान कानपुर में है। उनके लिए छड़ी, ट्राइसाइकिल या जो दूसरे अंग निर्माण किए जाते हैं, उन्हें फ्री देने की सुविधा दी जाए। हमारे जैसे सांसदों के पास आए दिन विकलांग लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें ट्राइसाइकिल दिलवा दीजिए, कोई कहता है कि हमारा हाथ लगवा दीजिए, कोई कहता है हमारा पैर लगवा दीजिए।...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन्हें जो पैंशन दी जा रही है, वह नाकाफी है। सरकार ने विकलांग पैंशन देने का जो प्रावधान किया है, वह 50 प्रतिशत से ऊपर के विकलांगों के लिए है। उसमें छूट प्रदान की जाए। विकलांग विकलांग होता है। 25 से 100 प्रतिशत विकलांग को एक हजार रुपये के लगभग पैंशन दी जाए।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री से मांग करता हूं कि विकलांगों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें स्वावलम्बी तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा, पैंशन, आरक्षण में समुचित व्यवस्था की जाए तथा बैसाखी, ट्राइसाइकिल व कृत्रिम अंगों की उपलब्धता करवाई जाए।